Scheme to provide employment to Graduate Youth in Karnataka

4194. SHRI S. R. REDDY: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether any scheme has been drawn by the State of Karnataka to help in providing interim employment to graduate youths during the current financial year and has been sent to Central Government for its advice; and

(b) if so, whether the Central Government propose to give any financial assistance to the State Government for that scheme and if so, to what extent?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). In its annual plan proposals for 1978-79 the Government of Karnataka had included a scheme for offering stipendiary employment to unemployed Graduate and Diploma-holders. The State Government had sought Central assistance for the scheme. The Planning Commission did not approve the scheme as it did not regard it as one for productive employment.

Pump-set Manufacturing Capacity

4195. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the production capacity of pump-set manufacturing units;

(b) whether there is shortage of pump sets due to under production of pump-sets; and

(c) what steps have been taken to meet the growing demand of the agriculturists?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) The total installed capacity for pumps in the organised sector is estimated to be about 3,62,000 No. per year.

(b) No shortage of pump sets has been reported. Instead the existing installed capacity is not being fully utilised because of paucity of orders.

(c) Units in the organised sector as well as in the smalll scale sector are already capable of meeting the growing demands of the agriculturists.

Policy regardning Import of Second hand Machinery from Abroad

4196. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have issued any licence for import of second-hand machinery from abroad;

(b) if so, whether such import has resulted in any setback to the indigenous manufacturers;

(c) the type of second-hand machinery being imported and what is the foreign exchange involved; and

(d) what is the Government policy with regard to import of second-hand machinery from abroad?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): (a) to (d). Import licences are issued by the C.C.I. & E., Ministry of Commerce, who are collecting the requisite information. This will be placed on the Table of the House in due course.

उत्तर प्रदेश में हिण्डालकों को बिजली की सप्लाई

4197. **श्री किरंगी प्रसाद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बिजली की सप्लाई के प्रश्न पर हिण्डालकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख). "हिण्डालकों" को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के सम्बन्ध में केंद्रीय उद्योग मंत्री ने राज्य सभा में 20 जुलाई, 1978 को एक अतारांकित प्रश्न सं० 454 का उत्तर दिया था जो निम्न प्रकार है :—

"इस सम्बन्ध में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।"

अनुसंधान अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारियों को सेवाओं को नियमित किया जाना

4198. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में अनेक अनुसंधान अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गत 10 वर्षों से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा 30 जून, 1978 को इनकी मंत्रालयवार तथा विभागवार संख्या क्या थी ;

(ख) इन अधिकारियों की सेवा को नियमित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन अधिकारियों के लिए इस समय पदोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध हैं तथा क्या कोई निश्चित समय निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत सरकार इनको स्थायी कर देगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय आर्थिक सेवा तथा सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड–IV को पुनः संरचना किए जाने के एक प्रस्ताव पर कोई अन्तिम निर्णय होने तक, इनमें से कुछ पदों को जो इन सेवाओं के ग्रेड–IV में हैं, समय-समय पर पदोन्नति द्वारा तदर्थ आधार पर भरा जाता रहा है। 30–6–1978 को मंत्रालय/विभागवार ऐसी नियुक्तियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध में दिया गया है, जो 10 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से चल रही हैं ।

(ख) और (ग) . ऐसे अधिकारियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड–IV के ऐसे पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। इन सेवाओं के ग्रेड–IV को पुनः संरचना किए जाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद, तदर्थ नियुक्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा । इसलिए, इन तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों को आगे पदोन्नति के और अवसर उपलब्ध कराए जाने अथवा ग्रेड-IV के पदों में उनके नियमित किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	मंत्रालय/ विभाग का नाम	10 वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर धारित भा०आ०से० के ग्रेड–IV के पदों की संख्या	10 वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर धारित भा० सां०से० के ग्रेड-IV के पदों की संख्या
1	2	3	4
1	योजना आयोग	22	5
2	गृह मंत्रालय	1	1
3	श्रम मंत्रालय	9	6
4	आर्थिक कार्य विभाग	2	
5	कृषि विभाग	4	3
6	वाणिज्य मंत्रालय	5	1
7	उद्योग मंत्रालय	2	1
8	सांख्यिकीय विभाग		10
9	पर्यटन विभाग		1
10	खान विभाग	..	1
11	पूर्ति विभाग	..	1
	कुल योग	45	30

News Item Captioned Million Tonues of Steam Coal goes to Fake Users

4199. SHRI PRADYUMNA BAL:
SHRI MAHI LAL:
SHRI JANARDHANA POOJARY:
SHRI JYOTIRMOY BOSU:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a news item which appeared in the Hindustan Times dated the 23rd July, 1978 under the caption 'Million tonnes of steam coal goes to fake users';

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the steps taken by Government in the matter?